वे नोट दिखाये थे कि इसकी जांच करें लेकिन उसकी जांच नहीं हुई जब कि 50 रुपए के जाली नोट बराबर छापे जा रहे हैं। क्या जो ऐसी प्राइवेट प्रेसें चल रही हैं उनको पकड़ने के लिए आपने कोई कार्यवाही की है या आपके पास कोई ऐसी मशीनरी है जो उनको पकड़ सके ? क्या इसका प्रबंध आप करेंगे ?

MR. CHAIRMAN: The question relates to Government press and not private press. Question disallowed. Now we take up Papers to be laid on the Table.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Cess on ex-factory value of output of Industrial Units for research and development

*221: SHRI YALLA SESI BHUSHANA RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to levy a cess on the ex-factory value of the output of each industrial unit in the country in order to boost research and development and to sponsor research in the industrial sector;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Govt. propose to provide encouragement and incentives for indigenous research and development in the industrial field in preference to import of technology from other countries;

(d) if so, the details of the scheme, if any, formulated in this regard so far; and

(e) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) The proposal to creat a Technological Development Fund to support Research & Development Programmes of scheduled industries is under consideration of the Government. An amount of Rs. 100 crores per year is proposed to be provided to the Fund. The functions to be assigned to the proposed Fund include promotion of Research & Development work of national or industry-wise importance. The manner of raising the additional resources for the Fund is yet to be decided.

(c) and (d) To encourage R & D in industries, Government has taken several measures providing various types of incentives. Some of the measures are de-licensing of and preferential treatment in licensing of industries based on indigenous technology and appropriate fiscal incentives for expenditure incurred on science research and utilisation of indigenous technology.

(e) Does not arise in view of (c) and (d) above.

Advertisements and sponsored programmes on Doordarshan

*222. SHRI J. P. GOYAL:
SHRI RAM NARESH KUSHAWAHA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to increase the time slot advertisements and sponsored programmes on Doordarshan;

(b) if so, what percentage of the total programme time is presently allotted to the sponsored programmes and advertisement and to what percentage it is likely to be raised;

(c) whether, besides augmenting funds through advertisements and sponsored programmes, any attempt has been made to examine the social impact of the presentation of images and behaviour to promote sales through advertisements on the cross section of society;

(d) if so, what are the details thereof stating the reasons for the proposed increase in the time for sponsored programmes and advertisements; and

(e) whether Government propose to evolve a long-term policy with defined objectives of the media?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI AJIT PANJA): (a) There is no such proposal at present.

(b) Does not arise.

(c) Studies to evaluate the impact of advertising are envisaged.

(d) Does not arise.

(e) So far as advertisements and commercials are concerned there already exists a well defined Code of Commercial Advertising on Doordarshan as also guidelines for sponsored programmes.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कम्प्यूटरों का उपयोग

*223. **श्री शरद यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में कम्प्यूटरों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) क्या कम्प्यूटरों पर कार्य करने वाले व्यक्ति किसी बाहरी एजेंसी के हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) जो काम कम्प्यूटरों द्वारा किया जा रहा है क्या वही काम बिना कम्प्यूटर की मदद के कर्मचारियों द्वारा भी किया जा रहा है ; और

(घ) बैंक के कर्मचारियों को कम्प्यूटर चलाने आदि के लिए कहां-कहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है और क्या यह प्रशिक्षण आवश्यकतानुरूप है; यदि हां, तो इस कार्य को बाहर की एजेंसियों द्वारा करवाये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र की गयी सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों ने कम्प्यूटर और एडवांस लैजर पोस्टिंग मशीनों की खरीद पर 1984-85 में 506 लाख रुपये और 1985-86 में 2109 लाख रुपए खर्च किये थे । बैंक इन मशीनों को चलाने के लिए प्रायः अपने कर्मिकों को ही रखते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में, प्रारम्भिक अवस्था में, मशीनों को चलाने के लिए बाहरी विशेषज्ञों की तब तक सहायता ली जाती है जब तक बैंक कार्मिक प्रणाली से परिचित नहीं हो जाते । प्रारम्भ में लैजर-पोस्टिंग मशीनों और कर्मचारियों द्वारा एक साथ काम किया जाता है । जब प्रणाली ठीक तरह से स्थिर हो जाती है तब उसके बाद हाथ से काम करना बंद कर दिया जाता है ।

बैंकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में निर्णय परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किया जाता है । कम्प्यूटरों और एडवांस लैजर पोस्टिंग मशीनों में कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए, बैंक कम्प्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन लि०, राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान और भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय जैसी संस्थाओं से, जहां प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध हैं, सहायता ले रहे हैं